प्राक्कथन

आर्थिक समीक्षा सरकार और सरकार से बाहर के अनेक सहयोगियों के साथ-साथ विदेश स्थित विश्लेषणकर्त्ताओं का सामूहिक प्रयास है। लेकिन, सबसे अधिक यह समीक्षा आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग के समर्पित कर्मचारियों के परिश्रम का परिणाम है। मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और सभी समय सीमाओं को प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया, और विभिन्न नियमों एवं व्यक्तियों से निभाते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया।

सभी आर्थिक समीक्षाओं पर तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार की छाप होती है। यही बात इस समीक्षा के साथ भी है। लेकिन परिवर्तन करने की इच्छा का निरंतरता बनाये रखने की जरूरत के साथ संतुलन होना चाहिए ताकि समय, सनक, फैशन और राजनीति की कसौटी पर खरी उतरी परंपराओं का सम्मान किया जा सके और उनसे सीख ली जा सके।

अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक से प्रेरित हो कर यह समीक्षा अपनी पूर्ववर्ती समीक्षाओं से संरचनागत दृष्टि से भिन्न है और इसे दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड एक में दृष्टिकोण और संभावनाओं पर चर्चा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण नीतिगत सरोकारों की चर्चा करने वाले अनेक विश्लेषणात्मक अध्याय शामिल हैं। खंड दो में अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुए हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है और सभी सांख्यिकीय सारणियां एवं आंकड़े दिये गये हैं। एक तरह से, खंड 1 दूरदर्शी है लेकिन हालिया घटनाक्रम से हासिल नज़रिए से जो सीखा गया है, वह खंड 2 का विषय है।

इस समीक्षा के खंड 1 की विषय सामग्री तय करते समय एक चुनौती यह थी कि भावी पीढ़ियों के धुंधले से दावों का, वर्तमान समय की महत्वपूर्ण और स्पष्ट मांगों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए? दूसरी तो स्थायी चुनौती है: गहराई या विस्तार?

जॉन मेनर्ड कीन्ज़ की एक मशहूर उक्ति है कि ''महत्वपूर्ण'' और ''अत्यावश्यक'' के बीच अन्तर करना जरूरी होता है। ऐसे मौके पर जब एक नई सरकार सत्तासीन है और अपना पहला पूरा बजट प्रस्तुत करने जा रही है, समय एवं संसाधनों से जुड़ी कठिनाइयों को देखते हुए, इस समीक्षा पर कीन्ज़ की सलाह का अच्छा-खासा असर हुआ है। इस समीक्षा में, विस्तृत कार्य क्षेत्र रखने की भूल करते हुए भी वर्तमान का पक्ष लिया गया है, भले ही इसका परिणाम गहन विश्लेषण की तुलना में सरसरी परीक्षण करने की स्वतंत्रता लेना ही क्यों न रहा हो।

इस समीक्षा के मुख्य विषय हैं- ''अवसर पैदा करना और असुरक्षा के हालात कम करना''। विकास अनेक आर्थिक, और सच कहें तो कई अन्य उद्देश्यों को पूरा करने की पूर्वापेक्षा है। सच तो यह है कि विकास के लाभों को बढ़ाने के लिए सरकार की सहायक कार्रवाई की जरूरत होगी, लेकिन, विकास के बिना आमदनी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब गरीबी और साधनहीनता कम करने पर चलने वाली बहस अधिकाधिक और आम तौर पर ''क्या'' के बारे में कम होती है और इस बारे में ज्यादा होती है कि व्यापक आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष सरकारी सहायता ''किस तरह बेहतरीन तरीके'' से काम आ सकती है। विकास और वितरण की तुलना करना एक गलत चयन है और हमेशा से गलत ही होना चाहिए था।

खंड एक की शुरूआत भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद आर्थिक दृष्टिकोण और संभावनाओं पर लिखे गए अध्याय से होती है जो ''अवसर पैदा करने और असुरक्षा के हालात कम करने'' पर केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा का संदर्भ तय करती है। इन मुद्दों पर आगे नौ अध्यायों में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

विकास के लिए वृहद आर्थिक स्थिरता और इसके लिए राजकोषीय स्थिरता की जरूरत होती है (अध्याय 2)। राजकोषीय रूपरेखा पर भी पुन:विचार किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह सरकार का पहला पूरा बजट है और क्योंकि चौदहवें वित्त आयोग की सूचित सिफारिशें भी हैं जो केन्द्र-राज्य के राजकोषीय संबंधों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकती हैं। इसके बाद ''हर आंख से आंसू पोंछने'' पर भी एक अध्याय है जहां इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि सहायता प्रदान करने का बेहतरीन तरीका क्या है और इस संबंध में प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है।

इन अध्यायों में इन विषयों पर बात की गई है: रुकी हुई परियोजनाओं की स्थिति और भविष्य में निजी और सरकारी निवेश पर उनके प्रभाव (अध्याय-4); बैंकिंग व्यवस्था की संक्षिप्त स्थिति और इसके सुधार के निहितार्थ (अध्याय-5); और भारत के भावी विकास को प्रेरित करने में रेलवे की भूमिका (अध्याय-6)। ''मेक इन इंडिया'' के नारे को लेकर बड़ी अकादमिक परिचर्चा हो रही है जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच चल रही बहस पर प्रकाश डाला जा रहा है और परिवर्तनकारी क्षेत्रों के बारे में नई सोच सामने आ रही है (अध्याय-7)। इन क्षेत्रों पर चर्चा को पूरा करने वाला एक ऐसा अध्याय भी है जो कृषि क्षेत्र में मौजूद हजारों बाजारों से हटकर एक साझा बाजार निर्मित करने के बारे में है (अध्याय-8)।

जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और यह चुनौतियां खड़ी करता है। इन पर अध्याय-9 में चर्चा की गई है। अध्याय 10 में केन्द्र-राज्य के राजकोषीय संबंधों में हो रहे जबर्दस्त परिवर्तन पर चर्चा की गई है। इसमें चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थों का आरंभिक विश्लेषण दिया गया है।

संक्षिप्त जानकारी चाहने वाले पाठकों के लिए दृष्टिकोण सम्बन्धी अध्याय उपयोगी होगा जबकि कई लोगों के लिए विस्तृत अध्याय काफी रुचिकर होंगे। खंड-1 में कुछ पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन जब हम अनेकानेक पाठकों के लिए लिखते हैं तो ऐसा होना अपरिहार्य है।

इस समीक्षा में अकादमिक और नीतिगत दोनों ही स्वरूप के नए विचारों और नए नज़रिए पर बल दिया गया है। समय और संसाधनों की कमी का अर्थ है कि नए विचार संभवत: कठोर शैक्षिणक मानकों पर खरे न उतर पायें। लेकिन नीति पर नई रोशनी डालने के उद्देश्य से हमारा रवैया यही रहा है कि नए आंकड़े प्राप्त किए जाएं अथवा पुराने आंकड़ों को नए रूप में पेश किया जाए ताकि उन में संबंध तय किया जा सके और जहां भी संभव हो, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके। हमारा उद्देश्य है कि नई बहस और परिचर्चा शुरू की जाए जिससे नीति निर्माण की प्रक्रिया समृद्ध हो और उम्मीद है कि इसके परिणामों में सुधार होगा।

इस समीक्षा में, इसकी गंभीरता बनाए रखते हुए, शुष्क अर्थशास्त्र को अखबारी लेखों (या कहें तो, ब्लॉग) जैसा ही दिलचस्प बनाने का प्रयास करते हुए, इसे पठनीय बनाने की कोशिश की गई है। प्रिय पाठक, यह विषय शुष्क हो सकता है, लेकिन नीरस नहीं होना चाहिए।

अरविन्द सुब्रह्मण्यन
मुख्य आर्थिक सलाहकार,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।